

आमृत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 13

लखनऊ, मंगलवार 07 जुलाई 2026 से 13 जुलाई 2026 तक

पृष्ठ—8

मूल्य : एक रुपया

श्रद्धालु, अयोध्यावासी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के नतीजों को लेकर उत्सुक

लखनऊ/अयोध्या। अयोध्या में राम लला के प्रति भक्ति भाव के बीच श्रद्धालुओं और आम लोगों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक के नतीजों को लेकर खासी उत्सुकता दिखी। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से उपजे विवाद के बीच आयोजित इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी हर छोटी-बड़ी हलचल जाने के लिए श्रद्धालु और स्थानीय लोग सुबह से ही टेलीविजन और मोबाइल की स्क्रीन से चिपके नजर आए। विभिन्न मंदिरों के पुजारी धीमी आवाज में घटनाक्रम पर चर्चा करते दिखे, जबकि श्रद्धालु चाय की दुकानों के बाहर रुककर बैठक से जुड़ी जानकारी का इंतजार करते नजर आए। कई लोगों का मानना था कि इस बैठक के नतीजों से भक्तों का भरोसा बहाल हो सकेगा। राम मंदिर के बाहर का

माहौल काफी शांत था। जो लता मंगेशकर चौक आमतौर पर पर्यटकों से भरा रहता है, वहां सोमवार को बहुत कम लोग दिखाई दिए। राम पथ पर दोपहर की तेज धूप में तीर्थयात्रियों के छोटे-छोटे समूह चुपचाप आते-जाते नजर आए। वहीं, पूजा सामग्री, प्रसाद, मिठाई और अन्य दुकानों पर इक्का-दुक्का श्रद्धालु ही दिखे। इलाके के होटल-रेस्तरां में भी सन्नाटा था। हालांकि, दुकानदारों ने ग्राहकों की संख्या में आई इस कमी के लिए उमस भरी गर्मी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पिछले महीने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी थी। करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के केंद्र राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर यकीन

करना अयोध्या के बहुत से लोगों के लिए मुश्किल था। राम पथ के पास स्थित एक दुकान के मालिक ने कहा हमने कभी नहीं सोचा था कि लोग भगवान राम के चरणों में



चढ़ाए गए पैसे की चोरी कर सकते हैं। यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मध्यप्रदेश से आए श्रद्धालु वीरेंद्र कुमार ने कहा हमने पूजा-अर्चना के बाद दान देने की योजना बनाई थी। अब हम सोच रहे हैं कि यह पैसा किसी वृद्धाश्रम

को दे दें। अगर मंदिर में दिया गया दान भी सुरक्षित नहीं है, तो इनसान को दोबारा सोचना पड़ता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि भगवान राम में उनकी अटूट आस्था है। बैरागी अखाड़े के पुजारी सोमेश्वर दास ने कहा सरकार ने गिरफ्तार आरोपियों से नकदी बरामद कर ली है, लेकिन ये सभी छोटे-मोटे लोग हैं। ट्रस्ट की बैठक में इस घोटाले के पीछे के बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला लिया जाना चाहिए। स्थानीय निवासी नितिन पांडे ने कहा, "भगवान राम सब कुछ देख रहे हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। उनकी मर्जी से ही यह चोरी सामने आई है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें उनकी करनी की सजा जरूर

मिलेगी।" दिन जैसे-जैसे दिन बीतता गया, वैसे-वैसे अयोध्या में हर जगह चर्चा का विषय ट्रस्ट की बैठक पर ही केंद्रित होता गया। राम मंदिर चढ़ावा 'चोरी' मामले की पड़ताल के लिए १३ जून को गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने २३ जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके आठ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी तीन नये निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में तीन नये निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर अब ५६ हो जायेगी। उपाध्याय ने प्रेसवार्ता में कहा कि तय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम २०१६' के तहत इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सम्बन्धित संस्थानों को 'आशय पत्र' और संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि

राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि जिन संस्थानों को मंजूरी दी गयी उनमें एक कृषि-केंद्रित विश्वविद्यालय भी शामिल है जिसे दिल्ली के 'स्वामी



ब्रह्मानंद सरस्वती चौरिटेबल ट्रस्ट' कानपुर नगर जिले में बिल्हौर तहसील के गदनपुर अहार गांव में ५१.७३६ एकड़ जमीन पर स्थापित करेगा। उपाध्याय ने बताया कि इस विश्वविद्यालय का मकसद राज्य में कृषि शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना है तथा इसके लिए

'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम' में संशोधन से सम्बन्धित एक अध्यादेश लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दूसरा निजी विश्वविद्यालय गाजियाबाद की 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी' द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र के डासना गांव में २६.२६५६ एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। उपाध्याय ने बताया कि तीसरा विश्वविद्यालय फतेहपुर के 'एंग्लो सेंट क लेज' द्वारा फतेहपुर दक्षिणी में २०.४५ एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर ५६ हो जाएगी।

उच्च न्यायालय का राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरा-फेरी की स्वतंत्र जांच का आदेश देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है। न्यायमूर्ति राजन रय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित अशोक द्वारा दायर

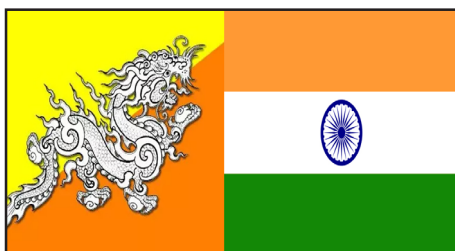
जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने और मंदिर के वित्तीय मामले का अडिट भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैंग) से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। पीठ ने याचिका के गुण-दोष की जांच करने से इनकार करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया।

ताजमहल मामले में नोटिस जारी

लखनऊ। ताजमहल पर हिंदू समुदाय की दावेदारी को लेकर एक बार फिर कानून दांवपेंच शुरू हो गया है। इसे भगवान शिव का मंदिर बताते हुए एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एसआई सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। ताजमहल परिसर के भीतर 'भगवान श्री अग्नेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विशाजमान तेजो महालय' मंदिर होने का दावा करते हुए यह याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को इस मामले में

अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इससे पहले आगरा की निचली अदालत ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक या एडवोकेट कमिशनर के जरिए सर्वे कराने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इस याचिका में मांग की गई है कि आगरा की जिला अदालत और अतिरिक्त जिला जज की ओर से पारित किए गए पुराने आदेशों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। इसके अलावा ताजमहल परिसर की वास्तविकता और धार्मिक प्रतीकों की जांच के लिए एडवोकेट कमिशनर के जरिए निष्पक्ष सर्वेक्षण कराया जाए।

भूटान ने ई20 पेट्रोल लेने से मना किया



नई दिल्ली। एक तरफ जहां भारत में २० फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर विरोध चल रहा है वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश भूटान ने भारतीय ऑयल कंपनियों का ई२० पेट्रोल लेने से मना कर दिया है। भूटानी मीडिया 'द भूटानीज' की रिपोर्ट के मुताबिक, भूटान ने भारत से अनुरोध किया है कि जब तक भारतीय बाजार में नॉर्मल पेट्रोल उपलब्ध है, तब तक उन्हें बिना मिलावट वाला पुराना पेट्रोल ही सप्लाई किया जाए।

सम्पादकीय

विझिंजम पोर्ट सौदा: क्या अनुबंधों से ऊपर हैं कॉरपोरेट हित?

केरल के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में अडानी समूह द्वारा अपनी ४६ प्रतिशत हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड की मेडिटेरिनियन शिपिंग कंपनी (MSC) को बेचने के फैसले ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद का केंद्र केवल हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं, बल्कि यह है कि क्या इस प्रक्रिया में अनुबंध की शर्तों और सरकारी स्वीकृतियों का पालन किया गया। केरल सरकार का दावा है कि परियोजना समझौते के अनुसार २५ प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी बेचने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। साथ ही, विझिंजम एक रणनीतिक बंदरगाह होने के कारण किसी विदेशी कंपनी को बड़ी हिस्सेदारी देने से पहले सुरक्षा संबंधी मंजूरी भी जरूरी मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी अनुबंध में ऐसी शर्त होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर, अडानी पोर्ट्स का कहना है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है और हिस्सेदारी हस्तांतरण की अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा चुका है। हालांकि, इस घटनाक्रम ने यह बहस तेज कर दी है कि क्या बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां पहले सौदों की घोषणा कर देती हैं और सरकारी मंजूरी बाद में केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। अब नजर राज्य और केंद्र सरकारों पर है। उनका फैसला केवल इस सौदे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि सार्वजनिक परियोजनाओं से जुड़े अनुबंधों, पारदर्शिता और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का कितना सम्मान किया जाता है। यदि नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो इससे भविष्य में सार्वजनिक-निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं।

रोजगार के आंकड़ों की चमक और जमीनी हकीकत

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) की ताजा रिपोर्ट में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रोजगार की स्थिति को लेकर कई सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल में भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की हिस्सेदारी में सुधार हुआ है और बेरोजगारी दर घटकर ४.६ प्रतिशत रह गई है। पहली नजर में ये आंकड़े उत्साहजनक दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर रोजगार की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल सामने आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि बड़े शहरों में ५५ प्रतिशत से अधिक श्रमिक नियमित वेतनभोगी हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जिन्हें भविष्य निधि (पीएफ), पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और सवैतनिक अवकाश जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी तरह गिग और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार में बढ़ोतरी को भी रोजगार वृद्धि के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि इन क्षेत्रों में नौकरी की स्थिरता और श्रम अधिकार अब भी सीमित हैं। महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर २७.२ प्रतिशत होने को सकारात्मक उपलब्धि बताया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी असंगठित क्षेत्र या कम अथवा बिना वेतन वाले कार्यों में लगी हैं। साथ ही, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलने की समस्या भी बरकरार है। रिपोर्ट में बेरोजगारी दर में कमी का उल्लेख है, लेकिन अर्ध-रोजगार (Underemployment) और योग्यता से कम स्तर की नौकरियों में काम करने वाले युवाओं की स्थिति पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई है। आज बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवा अपनी योग्यता से कम स्तर के कार्य करने को विवश हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह रिपोर्ट केवल दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तक सीमित है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की रोजगार स्थिति इससे अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। रोजगार की स्थिति का मूल्यांकन केवल रोजगार पाने वालों की संख्या से नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, आय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। इसलिए सकारात्मक आंकड़ों के साथ-साथ इन चुनौतियों पर गंभीर नीति-स्तरीय विमर्श भी आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में आम की दावत, सियासत पर चर्चा! मुख्यमंत्री योगी से मिलकर नितिन नवीन ने सेट किया मिशन २०२७ का टारगेट

लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दो दिनों के दौरे के दौरान वे लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं और बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का मंत्र दे रहे हैं। अपने इस दौरे में नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्हें आम की दावत भी दी गई, जिसका उन्होंने पूरा आनंद लिया। इसके अलावा, उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी २०२७ में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर बातचीत की। दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा की। इस बैठक में सभी ने अपने पुराने संगठनात्मक अनुभवों को साझा किया और आने वाले चुनाव में पार्टी को पहले से भी बड़ी जीत दिलाने की योजना पर विस्तार से बात की। बैठक शुरू होने से पहले भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उनका स्वागत किया। भाजपा सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को ज्यादा सक्रिय करने और २०२७

के चुनावी रोडमैप पर चर्चा की गई। हालांकि, वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के सालों के संगठनात्मक अनुभव और उनकी कार्यशैली से मिली

की जनता गुंडाराज, माफियाराज, परिवारवाद और दंगों की राजनीति बिल्कुल नहीं चाहती, बल्कि वे विकास, अच्छा शासन और सुरक्षा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के रहने से ही प्रदेश समृद्ध होगा, जबकि सपा की सरकार आने पर अराजकता



सीख संगठन को और ज्यादा मजबूत व असरदार बनाने में मदद करेगी। वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में हुई इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने अच्छे कामों के दम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में २०२७ में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश

और जमीन कब्जाने के मामले बढ़ेंगे। मौर्य ने दावा किया कि अगले २१ सालों तक समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रहेगी और देश व राज्य को २०४७ तक विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सरकार और संगठन मिलकर २०१७ जैसी बड़ी जीत को २०२७ में भी दोहराएंगे। इस खास बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, भूपेंद्र सिंह चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, डॉ. रमापति राम त्रिपाठी और डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

लंच, चाय और आम पार्टी के बहाने भाजपा का चुनावी संदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार को आयोजित लंच, मैंगो पार्टी और चाय पार्टी महज सामाजिक मुलाकातें नहीं थीं, बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं की साझा मौजूदगी ने स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी २०२७ के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व होता है। वर्ष २०२२ के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केशव प्रसाद मौर्य के आवास जाना जिस तरह चर्चा का विषय बना था, उसी संदेश को इस बार अधिक व्यापक रूप में दोहराया गया। मुख्यमंत्री आवास पर लंच, ब्रजेश पाठक के यहां मैंगो पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य के यहां चाय पर मुलाकात ने उन तमाम अटकलों को विराम देने की कोशिश की, जिनमें भाजपा नेतृत्व के भीतर

मतभेदों की चर्चा होती रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। संगठनात्मक बैठकों,

में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का एक मंच पर सहज और आत्मीय दिखाई देना कार्यकर्ताओं के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों के लिए भी



वरिष्ठ नेताओं से विमर्श और सहयोगी दलों के साथ संवाद के जरिए पार्टी ने यह संकेत दिया कि वह चुनाव को केवल सत्ता बरकरार रखने की चुनौती नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक अभियान के रूप में देख रही है। ताज होटल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों के साथ हुई बैठक ने भी इस संदेश को और मजबूत किया कि भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व की एकजुट छवि हमेशा महत्वपूर्ण रही है। ऐसे

एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक रूप से एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहता है। हालांकि चुनावी सफलता केवल प्रतीकात्मक आयोजनों से तय नहीं होती। अंततः जनता का निर्णय सरकार के कामकाज, विकास, कानून-व्यवस्था, सामाजिक समीकरण और चुनावी मुद्दों पर निर्भर करेगा। फिर भी यह स्पष्ट है कि भाजपा ने इन आयोजनों के माध्यम से चुनावी माहौल बनाने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और नेतृत्व की एकजुट तस्वीर पेश करने की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में रविवार को दिखाई गई यह राजनीतिक तस्वीर केवल लंच, चाय और आम पार्टी तक सीमित नहीं थी। इसे २०२७ के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक संदेश के पहले सार्वजनिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

भाजपा में 'सत्ता का संघर्ष', अयोध्या मुद्दे पर आस्था से किया जा रहा है समझौता : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संगठन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 'सत्ता का संघर्ष' होने का आरोप लगाया एवं कहा कि अयोध्या में लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं से समझौता किया जा रहा है। यादव ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर दल के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रेसवार्ता में भाजपा पर आरोप लगाया कि इस पार्टी का नेतृत्व लोगों की धार्मिक आस्था की रक्षा करने से ज्यादा अंदरूनी झगड़े को लेकर फिक्कमंद है। उन्होंने आरोप लगाया, "हमारी आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, फिर भी वे चुप हैं। डबल इंजन वाली सरकार (उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार) एक साथ नहीं चल रही हैं। दोनों इंजन टकरा रहे हैं। सत्ता का संघर्ष है। उन्हें आस्था या भक्ति की कोई

चिंता नहीं है। यादव ने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोग खजाने के लालच में 'अंधे' हो गए हैं और यह झगड़ा भाजपा के अंदर नियंत्रण की लड़ाई को जाहिर करता है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कथित चढ़ावा चोरी मामले की विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) की जांच खुद भाजपा की अंदरूनी खींचतान को उजागर करती है। उन्होंने कहा, "अगर यह प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई या आयकर विभाग का मामला होता, तो जांच दिल्ली के हाथ में होती। मगर इससे पहले कि दिल्ली इस बारे में सोच पाती, लखनऊ ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। यह सत्ता के संघर्ष की वजह से हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदू धर्मगुरुओं और संस्थाओं से इस विवाद पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया, "मैं दुनिया भर के राम भक्तों, अयोध्या के संतों, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, अयोध्या के नागरिकों और पीडीए (पिछड़े, दलित और

अल्पसंख्यक वर्ग) समाज से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूं। भाजपा मिथ्या प्रचार करने के



लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का जिक्र करते हुए दावा किया कि इससे पार्टी संगठन और राज्य सरकार के बीच जारी अनबन सामने आ गई है। उन्होंने कहा, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो ऐसा लगा जैसे लखनऊ में कर्फ्यू लगा दिया गया हो। दरअसल, संगठन और सरकार के बीच बहुत बड़ा झगड़ा है। सपा प्रमुख ने भाजपा अध्यक्ष के अपने लखनऊ दौरे के दौरान पार्टी नेताओं के साथ एक चाय की

दुकान पर चाय पीने को लेकर तंज किया और कहा, "जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता, तो आप चाय पीते हैं। यादव ने सपा के सदस्यता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी इस मुहिम को तेज करके अपने जमीनी नेटवर्क को मजबूत करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश करते हुए आरोप लगाया कि राज्य की मौजूदा भाजपानीत सरकार अब भी उनके शासनकाल में शुरू की गयी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है। यादव ने राज्य सरकार पर जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन को समर्पित एक संग्रहालय है मगर भाजपा ने समाजवादी आंदोलन से अपनी नफरत की वजह से इसे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा का गठन हुआ था, तब इस बात पर बहस हुई थी कि

भाजपा का रास्ता क्या होगा तथा उसने तय किया था कि उनका रास्ता धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होगा। यादव ने कहा, उनके पास दिखाने के लिए कोई समाजवादी नेता या चेहरा नहीं था। जब उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वह उन्हीं के नक्शेकदम पर समाजवादी आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, आज वे (भाजपा के नेता) मुस्लिम भाइयों से इतनी नफरत कर रहे हैं जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले प्रस्तावक भी एक मुस्लिम था। सपा प्रमुख ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी के कई नेता अपना चुनाव क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें उन्हीं चुनाव क्षेत्रों से फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। हम उन्हें वहीं हराने के लिए तैयार हैं। यादव ने इंजीनियरिंग शिक्षा और मूलभूत ढांचे को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की।

यूपी में स्टार्टअप और डेटा सेंटर्स के लिए नई नीतियां मंजूर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, श्रम मंत्री अनिल राजभर और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल की बैठक में हुये निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने निवेश, उद्योग, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फलों पर मुहर लगाई। इनमें उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन-2026, नई डेटा सेंटर नीति, मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन पशुधन बीमा योजना के राज्यव्यापी विस्तार तथा शाहजहांपुर की जलालाबाद नगर पालिका का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने का निर्णय प्रमुख रहा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष 'स्टार्टअप मिशन निदेशालय' के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या को और बढ़ाने के लिए 'इनक्यूबेटर्स' तथा 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन-2026' के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया जाएगा, जबकि मिशन के प्रभावी संचालन के लिए एक

कार्यकारी समिति का गठन होगा। अभी तक स्टार्टअप कार्यक्रम का संचालन केवल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन (यूपीएलसी) करता था, लेकिन अब इसके लिए एक अलग समर्पित इकाई होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सहित अन्य अधिकारी और



कर्मचारी तैनात होंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने समाप्त हो चुकी नीति के स्थान पर 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026' और नई 'डेटा सेंटर नीति' से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि डेटा सेंटर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भारत का अधिक से अधिक डेटा देश में ही सुरक्षित रहे, इसके लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ७५ जिलों में बीमा योजना: सरकार ने 'मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन पशुधन बीमा योजना' को प्रदेश के सभी ७५ जिलों में लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम का ८५ प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी, जिससे पशुपालकों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। होमगार्ड्स को तोहफा: प्रदेश के लगभग ६६ हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीति दी गई है। श्रमिकों

के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में पांच-पांच एकड़ भूमि पर ईएसआई (ESI) अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में १३ एकड़ भूमि पर ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जहां ५० प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। निजी क्षेत्र में तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को स्वीति दी गई है, जिनमें महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय (बिल्हौर, कानपुर), अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय (गाजियाबाद) तथा ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले-

लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले दलों ने हमेशा राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और उन्हें अयोध्या पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरा देश और सनातन समाज जानता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने वर्षों तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसका राजनीतिक

शामिल हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद का नाम बदलकर अब 'परशुरामपुरी' करने का निर्णय लिया गया है। गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने तथा उनकी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए अवस्थापना विकास निधि से धन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। वाराणसी रोप-वे: कैबिनेट ने वाराणसी रोप-वे परियोजना के लिए चिन्हित नजूल भूमि

‘मंदिर पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं’

परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यही वे लोग हैं जिन्होंने निहत्थे रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं और अयोध्या को रक्तंजित किया। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने भगवान



श्रीराम के जन्मस्थान पर भी सवाल उठाए थे और न्यायालय में भी इसी तरह का रुख अपनाया था। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के एक कथित वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें भगवान राम के दोबारा वनवास जाने जैसी बातें कही गईं। उन्होंने आरोप

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा, बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026, पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय के बाद शेष धनराशि के उपयोग, सातवें वेतन आयोग के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पेंशन के पुनरीक्षण सहित कई प्रशासनिक और सेवा नियमावली संशोधनों को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इन दूरगामी निर्णयों से प्रदेश में भारी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

लगाया कि सपा ने हमेशा भगवान राम और सनातन संस्कृति के खिलाफ बेबुनियाद टिप्पणियां कर माहौल खराब करने की कोशिश की है। डिप्टी सीएम ने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे और वक्फ से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जुटाया गया धन कहां गया। साथ ही वक्फ से जुड़े कथित घोटालों और मदरसों की फंडिंग के स्रोत पर भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता सनातन संस्कृति को बदनाम करने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेगी और विपक्ष को इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए।

घरेलू सिलेंडर दो हजार का मिलता- मोदी

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट के प्रबंधन को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने देश की जनता को बताया कि उनकी सरकार ने कितने प्रभावशाली तरीके से ऊर्जा संकट का प्रबंधन किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि अगर सरकार ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं करती तो देश में घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर के दाम दो हजार रुपए तक पहुंच जाते। वैसे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम तीन हजार रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी दावा किया कि २१वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो गया था लेकिन भारत ने इस संकट को भी छोटा कर दिया। मोदी ने कहा, 'भारत ने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया। युद्ध के कारण जो हालात

पैदा हुए, उसके कारण घरेलू गैस के दाम दो हजार रुपए तक जा सकते थे। सरकार ने इसको लेकर बेहतर मैनेजमेंट किया। इसी का परिणाम है, सिलेंडर ६५० रुपए



के करीब मिल रहा है'। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को राजस्थान के दौरे पर पहुंचे थे। दोपहर करीब १२ बजे वे बालोतरा के पंचपदरा पहुंचे। वहां देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इससे पहले जब इस रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था तब इसमें आग लग गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल

तरीके से जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रही। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर में हवाईअड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संकट की बात करते हुए तेल कंपनियों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के बीच पेट्रोल, डीजल से ही कंपनियों को ७५ हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मोदी ने कहा कि ये घाटा इतना बड़ा था कि एक नई रिफाइनरी बन जाए। ये घाटा सरकारी खजाने से भरा गया। मोदी ने यह भी दावा किया कि युद्ध के समय भारत की दूसरे देशों से दोस्ती बहुत काम आई। उन्होंने कहा कि पहले जहां २५ देशों से ईंधन खरीदते थे, वह ४० देशों तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिखा।

इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार की सफाई

नई दिल्ली। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मामले में सरकार घिरी है। देश भर से सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, जिनमें इथेनॉल मिले पेट्रोल से गाड़ियों को होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। लोग बता रहे हैं कि इससे गाड़ियों के इंजन को नुकसान हो रहा है और माइलेज कम हो रही है। भाजपा के समर्थक राइटविंग इन्फ्यूएंसर्स सबसे ज्यादा सक्रिय विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सरकार की ओर से शनिवार को सफाई दी गई। सरकार के विशेषज्ञों सहित इस मामले के जानकारों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मारुति कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने भी प्रेस से बात की। सरकार की ओर से बताया गया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम रातों रात नहीं हुआ। यह एक जांची परखी, साइंटिफिक और चरणबद्ध तरीके से की गई प्रक्रिया है। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसका टेस्ट कर चुकीं

हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का देश भर में हो रहे विरोध पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की प्रेस कन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल २०१३ और २०१४ के दौरान पेट्रोल में सिर्फ डेढ़ फीसदी इथेनॉल मिलाया



जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में २० फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है, जिसे ई२० पेट्रोल नाम दिया गया है। गौरतलब है कि २० फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भी पेट्रोल के दाम लगभग पूरे देश में सौ रुपए लीटर से ज्यादा हैं। गौरतलब है कि भारत में २० फीसदी इथेनॉल और ८० फीसदी पेट्रोल के मिश्रण वाले ई२० पेट्रोल का विरोध हो रहा है। खासकर २०२३ से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के

मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इस पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, मेटेनेंस का खर्च बढ़ गया और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार का कहना है कि इथेनॉल से माइलेज में मामूली कमी जरूर आती है, लेकिन इससे गाड़ी का पिकअप और इंजन परफॉर्मेंस बेहतर होता है। बहरहाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल वर्तिका शुक्ला ने बताया कि विशेष रूप से साल २०१८ में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को व्यवस्थित तरीके से सभी स्टेकहोल्डर्स के सामने चर्चा और विचार विमर्श के लिए रखा गया था। यह पूरा प्रोग्राम वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सियाम जैसी टॉप एजेंसियां इसकी बड़े लेवल पर टेस्टिंग कर चुकी हैं। वर्तिका शुक्ला के अनुसार, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का यह प्रोग्राम दुनिया भर में अपनाई जाने वाली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अनुरूप है।

साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन



निर्यातक देश बन गया है। मोदी ने कहा, 'हम मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ वह चिप भी बनाएंगे, जिनसे पूरी दुनिया चलती है'। उन्होंने कहा, '२० साल पहले मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई। उस समय की केंद्र सरकार बड़े बयान दे रही थी तो कई कंपनियां आई भी लेकिन केंद्र सरकार को उस समय क्या हो गया, उनके पैरों में बेड़ियां लग गईं और बात आगे नहीं बढ़ पाई'।

साणंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। साणंद में स्थित सीजी सेमी के ओएसएटी प्लांट में शनिवार से प्रोडक्शन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि इस प्लांट में हर साल २० करोड़ चिप बनेंगी। उन्होंने बताया कि यहां पर हर साल पांच सौ करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता और

खामेनेई की अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल

नई दिल्ली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को आखिरी विदाई के कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में जुटे। शिया परंपरा के मुताबिक काले



कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। इस दौरान लोगों ने 'खून बहेगा', 'अमेरिका मुर्दाबाद' और 'बदला, बदला' जैसे नारे भी लगाए। ईरान के अधिकारियों ने भी कहा कि खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। गौरतलब है कि राजधानी तेहरान में तीन जुलाई से खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो गई हैं, जो नौ जुलाई तक चलेगी। पहले दिन यानी शुक्रवार को कार्यक्रम में एक सौ से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत ने बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्यमंत्री पवित्रा मार्गेरिता को भेजा है। रूस, चीन और तुर्किए के टॉप लीडर्स ने भी इससे दूरी बरती। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर

के प्रतिनिधियों को भेजा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मानवता

के नाते ऐसा किया है। कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। गौरतलब है कि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले कतर में दोनों देशों के बीच दूसरे चरण की वार्ता हुई। बहरहाल, अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगभग पूरी कैबिनेट लेकर तेहरान पहुंचे। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ ने लिखा कि खामेनेई की बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और ईरान के साथ पूरे क्षेत्र पर उनके गहरे प्रभाव को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इस बीच ईरान के खुफिया मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए खामेनेई और दूसरे लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा।

टेलीग्राम के पीछे पड़ी सरकार

नई दिल्ली। नीट यूजी की परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर पाबंदी लगाने के बाद अब सरकार ने उसके लिए नया फरमान जारी किया है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के पायरेटेड वर्जन देने वाले चैनल्स और ग्रुप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। ऐसा होता है तो लोगों मुफ्त में फिल्में और ओटीटी के सीरीज नहीं देख पाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को कंपनी को नोटिस भेजा। मंत्रालय ने कहा कि टेलीग्राम अगले १५ दिन में पायरेटेड कंटेंट पर लिए एक्शन की रिपोर्ट सौंपे। टेलीग्राम को तीन दिन में सरकार का दूसरा नोटिस मिला है। इससे पहले टेलीग्राम को जो जुलाई को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें सूचना व प्रौद्योगिक मंत्रालय ने यूजरनेम फीचर और यूजर्स की प्राइवैसी पर सवाल पूछे थे। दूसरे

नोटिस को लेकर बताया जा रहा है कि सरकार ने टेलीग्राम से कहा वह एक्शन लेने के लिए शिकायतों का इंतजार न करें। सरकार ने कहा कि पायरेटेड कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर आने से रोकने के



लिए वह पुख्ता सिस्टम बनाए। सरकार ने कंपनी को बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, बट्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर और उनसे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ कदम उठाने का निर्देश दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसा कंटेंट मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आज : ट्रस्ट अध्यक्ष ने तोड़ी चुप्पी

लखनऊ। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उठे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सोमवार को होने जा रही अहम बैठक से ऐन पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह इस घटना से 'बहुत आहत' हैं और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस 'पाप' में शामिल लोगों को 'कड़ी से कड़ी' सजा दिलाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अतिथिगृह में अपराह्न तीन बजे होने वाली इस बैठक में मंदिर से चढ़ावा की कथित चोरी की जांच और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के मुद्दों पर अहम चर्चा होने की सम्भावना है। इस बैठक से ऐन पहले अपने एक बयान में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने राम मंदिर से चढ़ावा चोरी पर खुद को 'काफी आहत' बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों को 'कड़ी से कड़ी सजा' देने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे "हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है, उसको सजा दिलाएंगे। दास ने यह भी कहा कि यह मामला "करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिये। सूत्रों के मुताबिक गत २६ जून को सांस लेने में तकलीफ और संक्रमण की शिकायत पर महंत नृत्यगोपाल दास को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें गत तीन जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है, लेकिन उनके सोमवार को ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने की सम्भावना नहीं है और इसकी कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। सूत्रों के अनुसार पहले संकेत मिले थे कि वह अपने घर से वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब शामिल नहीं होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार में सचिव प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के

अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के भी वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार-विमर्श होने, दान की कथित चोरी के मामले में विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) की जांच की समीक्षा और त्यागपत्र स्वीकार



किए जाने की स्थिति में ट्रस्ट में अहम पदों पर नियुक्तियों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। पहले यह बैठक मणि रामदास छावनी में होनी थी, मगर सुरक्षा कारणों से बैठक की जगह बदलकर मंदिर परिसर में कर दी गई है। मंदिर परिसर के पास मीडिया समेत निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट

की इस बैठक से पहले इसके कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि के आवास पर बंद कमरे में एक बैठक हुई जिसमें विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इस चर्चा में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन, विहिप के महासचिव बजरंग बागड़ा और केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य दिनेश कुमार भी शामिल हुए। हालांकि बैठक में शामिल लोगों ने मीडिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच, अयोध्या के निवासियों और साधु-संतों ने कहा कि वे ट्रस्ट की बैठक के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। यहां राम पथ पर पूजा सामग्री बेचने वाली रीमा देवी ने कहा भगवान राम के मंदिर में हुई इस चोरी से अयोध्या में हर कोई दुखी है। हमारी बस यही इच्छा है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनकी पहचान हो और उन्हें सजा मिले। मंदिर की ओर जाने वाला राम पथ सोमवार को सुनसान लग रहा था। इस दौरान मंदिर की ओर

जाते हुए भक्तों के छोटे-छोटे समूह ही नजर आये। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गत १३ जून को गठित एसआईटी ने २३ जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके आठ नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं ने हटाए गए सीसीटीवी फुटेज को भी बरामद किया है, जिसमें कथित तौर पर आरोपी लोग मंदिर परिसर से बाहर निकलते समय रकम छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, मगर फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। सूत्रों के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विवादों में घिरे ये तीनों ट्रस्ट सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। बैठक के दौरान ट्रस्ट द्वारा जांच की प्रगति की समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद है।

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, ११ चौकी प्रभारियों का तबादलाय ६५ उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले

बाराबंकी। जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने ११ चौकी प्रभारियों का तबादला करते हुए उनके नए कार्यस्थल निर्धारित किए हैं। इसके अलावा करीब ६५ उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। वहीं पुलिस लाइन में तैनात एक उपनिरीक्षक को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी तबादला सूची के अनुसार, उपनिरीक्षक अमित कुमार को चौकी प्रभारी सुखीपुर से एसएसआई थाना लोनीकटरा, रवीन्द्र कुमार सिंह को चौकी प्रभारी बड़ेल (कोतवाली नगर) से चौकी प्रभारी सुखीपुर, संजय कुमार यादव को चौकी प्रभारी जेल (कोतवाली नगर) से चौकी प्रभारी

मोहिउद्दीनपुर (थाना सतरिख) और अभय गुप्ता को चौकी प्रभारी कस्बा (थाना मसौली) से चौकी प्रभारी छबील (थाना लोनीकटरा) बनाया गया है। इसी क्रम में अरुण सिंह



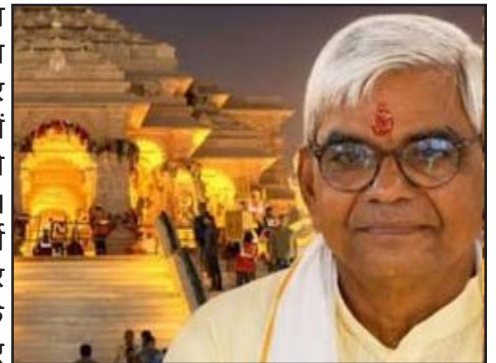
को चौकी प्रभारी छेदा से चौकी प्रभारी अलियाबाद (थाना दरियाबाद), विनय कुमार को चौकी प्रभारी कस्बा (थाना जैदपुर) से चौकी प्रभारी विशुनपुर (थाना देवा), संजय कुमार को चौकी प्रभारी मोहिउद्दीनपुर से चौकी प्रभारी जेल

(कोतवाली नगर), विपिन सिंह को चौकी प्रभारी छबील से चौकी प्रभारी कस्बा (थाना मसौली), राकेश कुमार तिवारी को चौकी प्रभारी अलियाबाद से चौकी प्रभारी छेदा, संजय कुमार को चौकी प्रभारी भानमऊ (थाना कोठी) से चौकी प्रभारी कस्बा (थाना जैदपुर) तथा संजय प्रसाद को चौकी प्रभारी विशुनपुर से चौकी प्रभारी भानमऊ भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा को चौकी प्रभारी बड़ेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी इस तबादला सूची को कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हरदोई के कृष्ण मोहन बने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव, जिले में खुशी की लहर

हरदोई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सोमवार को हुई अहम बैठक में हरदोई जिले के निवासी कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की खबर मिलते ही जिले में खुशी का माहौल बन गया। खास बात यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में दर्ज एफआईआर के वादी भी कृष्ण मोहन ही हैं। ट्रस्ट की बैठक में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। इसके बाद नई व्यवस्था होने तक ट्रस्ट ने कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। शाहाबाद तहसील से जुड़े कृष्ण मोहन का जिला मुख्यालय स्थित बहरा

सौदागर (सिनेमा रोड) में आवास है, जबकि उनकी ससुराल शहर के आवास विकास कॉलोनी में है। उनके नई जिम्मेदारी संभालने पर जिले के लोगों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता जताई। कृष्ण मोहन



सितंबर २०२५ में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य बनाए गए थे। ट्रस्ट सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उन्हें यह दायित्व सौंपा गया था। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के महाराष्ट्र कैडर के वर्ष १९७८ बैच के अधिकारी रहे कृष्ण मोहन ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की शिक्षा प्राप्त की। नागपुर में सेवा के दौरान उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव हुआ। वर्ष २०१२ में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। गृह जनपद हरदोई में भी वह नगर, जिला, प्रांत और क्षेत्र स्तर पर संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति को हरदोई के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

महिला लेखपाल ने एसडीएम पर छेड़छाड़ का

हरदोई। शाहाबाद तहसील में तैनात एक महिला लेखपाल ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सुशील कुमार मिश्रा पर चेंबर में बुलाकर छेड़छाड़, अशोभनीय हरकत करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने शाहाबाद कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पीड़ित महिला

लेखपाल के अनुसार, सोमवार शाम करीब ५:१० बजे उसे सूचना मिली कि एसडीएम ने अपने चेंबर में



बुलाया है। आरोप है कि चेंबर में पहुंचने पर एसडीएम ने उसे कार्यालय में कार्य करने के लिए कहा। जब उसने आंखों की समस्या

का हवाला देते हुए अपनी परेशानी बताई, तो एसडीएम ने कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला लेखपाल का कहना है कि घटना के दौरान उसने अपने पिता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार को फोन कर पूरी जानकारी दी। आरोप है कि जब उसके पिता एसडीएम के चेंबर पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। घटना के बाद महिला लेखपाल ने शाहाबाद

लगाया आरोप

कोतवाली पहुंचकर एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्र हो गए और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा का पक्ष जानने के लिए उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। उनका पक्ष प्राप्त होने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मोदी को धमकी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, छह जुलाई से छह दिन के विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। उससे पहले उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जान से मारने की धमकी मिली है। अस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस प्रधानमंत्री मोदी को दी गई धमकी की जांच कर रही है। हालांकि किसी के गिरफ्तार होने की सूचना नहीं है। शनिवार को 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' की रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह धमकी फेसबुक पर 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम के प्रचार से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे लिखी गई थी। पोस्ट के नीचे अबू मुस्तफा नाम के फेसबुक

अकाउंट से लिखा गया, 'स्टेडियम की छत कार्यक्रम के दौरान बंद रहनी चाहिए, नहीं तो वह ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आएगा'। बताया जा रहा है कि



जांच एजेंसियों ने उस पोस्ट से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान कर ली है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी आठ से १० जुलाई तक अस्ट्रेलिया में रहेंगे। 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम उनकी यात्रा के

दूसरे दिन यानी नौ जुलाई को मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में होना है। धमकी सामने आते ही इसकी जानकारी ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस को दे दी गई थी। अब तक पुलिस ने धमकी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुलिस किसी गिरफ्तारी की पुष्टि भी नहीं कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस, राज्य पुलिस और विशेष सुरक्षा इकाइयों समेत कई एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एसपीजी की टीम भी वहां पहुंच गई होगी, जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने हैं।

हार के बाद बदलेगी टीम इंडिया?

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टी२० अंतरराष्ट्रीय सीरीज अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द रहा, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की। अब दोनों टीमों ७ जुलाई, मंगलवार को ट्रेट ब्रिज में तीसरे टी२० में आमने-सामने होंगी, जहां भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है। दूसरे टी२० में भारतीय टीम ने तीन स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला किया था। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के साथ रवि बिश्नोई को भी अंतिम एकादश में जगह मिली, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैच के निर्णायक दौर में १७वां ओवर लेकर आए बिश्नोई ने लगातार दो बैक-फुट नो-बॉल फेंकी। इसके बाद मिली फ्री-हिट का इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाते हुए दो छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल २६ रन बने, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। रवि बिश्नोई ने अपने चार ओवर के स्पेल में ६०

रन खर्च किए और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। ट्रेट ब्रिज की परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि भारतीय टीम अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतर सकती है। ऐसे में रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रिंस यादव ने आयरलैंड



के खिलाफ अपने टी२० अंतरराष्ट्रीय पदार्पण मैच में तीन विकेट लेकर प्रभावित किया था। हालांकि उसके बाद उन्हें अंतिम एकादश से बाहर रखा गया। अब तीसरे टी२० में उनकी वापसी की संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीरीज के पहले दो मुकाबलों में भारत ने १८६ और १६० रन बनाए। पहला मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने १६०

रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। ऐसे में यदि तीसरे टी२० में भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो जीत की संभावनाएं मजबूत करने के लिए २०० या उससे अधिक का स्कोर खड़ा करना अहम माना जा रहा है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का मौका मिला, लेकिन पहले मैच में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। अब तीसरे मुकाबले में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्याश शेडगे, व शिंगटन सुंदर। हैरी ब्रुक (कप्तान), फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैटन, जैकब बेथेल, सैम कुरन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोश टंग, जॉर्डन कॉक्स, सन्नी बेकर, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स।

भाजपा ने मनाई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की १२५वीं जयंती, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को किया दोहराया

बाराबंकी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की १२५वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने

गुप्ता, नवनीत मिश्रा, प्रमोद गोस्वामी, शिवम सिंह राठौर, भोला गुप्ता, गौरव वर्मा, चन्द्रप्रकाश गुप्ता, संदीप पाण्डे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फतेहपुर: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर नगर के सिहाली रोड स्थित जन सहयोग केन्द्र में कार्यक्रम आयोजित किया



का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राम सिंह वर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने 'राष्ट्र प्रथम' के आदर्श को अपने जीवन का ध्येय बनाया। उन्होंने बंगाल के विभाजन के समय दूरदर्शी नेतृत्व और जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया, जो भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि आज वही बंगाल उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली भाजपा के सुशासन का साक्षी बन रहा है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य, जिला महामंत्री विजय आनंद बाजपेई, जिला उपाध्यक्ष मनीष परिहार, रचना श्रीवास्तव, जंगबहादुर पटेल, अंशु वर्मा, सिद्धार्थ अवस्थी, डॉ. सतीश चंद्र, संदीप गुप्ता, वैभव मिश्रा, चमन सिंह पटेल, सूरज सिंह, रूपेश प्रताप लक्की, आशुतोष अवस्थी, सर्वेश अवस्थी, पंकज

गया। इस दौरान भाजपा विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने 'एक निशान, एक विधान' की अवधारणा के तहत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए ऐतिहासिक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद उन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था और राष्ट्रहित के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता शीलरत्न मिहिर, राजीव नयन तिवारी, अर्जुन पंडित, एलजीपी के प्रदेश महासचिव अफसर अली, मंडल अध्यक्ष रंजीत लोधी, पिन्टू सिंह, सरोज वर्मा, हंसराज वर्मा, रजनीश वर्मा, सुधीर मिश्रा, रामचन्द्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

‘गौहत्या बंद होने तक जारी रहेगा धर्मयुद्ध’

सीतापुर। ज्योतिष एवं द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गविष्टि' गोरक्षार्थ-धर्मयुद्ध यात्रा शनिवार को अपने ६४ वें दिन हरदोई के रास्ते सीतापुर जनपद में प्रवेश कर गई। नैमिषारण्य की सीमा पर स्थित गोमती पुल पर बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कारागार राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी और स्थानीय संतों ने शंकराचार्य का अभिनंदन किया। ठाकुरनगर तिराहे पर आयोजित सभा में शंकराचार्य ने जनसमूह को 'गौमाता राष्ट्रमाता' और गोरक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने दो

टूक शब्दों में कहा कि यदि वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार ने गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया, तो वे ऐसी सरकार का खुलकर



विरोध करेंगे। उन्होंने साफ किया कि गौहत्या बंद होने तक यह धर्मयुद्ध जारी रहेगा। कार्यक्रम के बाद यात्रा मिश्रिख की ओर रवाना हो गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।

घर में घुसकर चोरी करने वाले तीन चोर गिरफ्तार, जेवर और नकदी बरामद



दौरान एसआई वासु कुमार के नेतृत्व में शहर कोतवाली की टीम-५ ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंदिरा नगर निवासी रवि गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता, अनीस पुत्र रईस तथा हरीपुरवा निवासी शिवम सिंह पुत्र धर्मैंद्र सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन जोड़ी पायल, १२ बिछिया, दो अंगूठियां और २,००० रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की अन्य घटनाओं में उनकी सलिप्तता की भी जांच कर रही है।

रदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र में घर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए जेवर और नकदी भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र के बिरहाना निवासी योगेंद्र प्रताप सिंह ने १ जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा ३०५(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के

श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि, छोटी काशी में डीएम-एसपी-सीडीओ ने परखी तैयारियां, दिए निर्देश

कृष्ण कुमार शुक्ला लखीमपुर खीरी। आगामी श्रावण माह के दौरान छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवड़ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु व्यवस्थाओं के



दृष्टिगत डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉ. ख्याति गर्ग, सीडीओ अभिषेक कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन मंदिर कॉरिडोर, परिसर तथा प्रमुख संपर्क मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की बारीकी से पड़ताल करते हुए साफ संदेश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी भी स्तर पर

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नक्शे के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की व्यवस्था का विस्तृत खाका समझा। श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों के निर्बाध आवागमन,



पार्किंग, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कॉरिडोर निर्माण की कार्यदायी संस्था को डीएम ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि

श्रावण माह शुरू होने से पहले सभी जरूरी अवशेष कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी एसडीएम स्तर से होगी और कार्यदायी संस्था प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। गुणवत्ता और समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीएम-एसपी ने मेला अवधि के दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सहायता तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं ताकि छोटी काशी में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन का अनुभव मिल सके। इस दौरान एसडीएम युगांतर त्रिपाठी, सीओ महक शर्मा, ईई पीडब्लूडी तरुणेन्द्र त्रिपाठी, जिला अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा, प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह, कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

शारदा नगर थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरियों से लोगों में आक्रोश

लखीमपुर खीरी। थाना शारदा नगर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि कई मामलों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार, बड़े गांव क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और गश्त के दावों के बावजूद चोरी की घटनाएं

थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जाटपुरवा गांव में वर्मा परिवार के घर से लगभग १० लाख रुपये मूल्य की नकदी एवं सामान चोरी होने की घटना सामने आई है। वहीं भरतपुर क्षेत्र में मछली पालन का कार्य करने वाले हिदायत नगर निवासी वसीम की भैंस भी चोरी हो गई, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों का कहना है कि थाना शारदा नगर पुलिस छोटे और गरीब लोगों पर

मुकदमे दर्ज करने में तत्पर दिखाई देती है, लेकिन चोरी जैसी गंभीर घटनाओं के खुलासे में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के कारण क्षेत्रीय जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से चोरी की घटनाओं के शीघ्र खुलासे तथा क्षेत्र में प्रभावी गश्त और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

अस्पतालों की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था परखी, कमियां मिलने पर दिए तत्काल सुधार के निर्देश

कृष्ण कुमार शुक्ला लखीमपुर। मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्युत सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को शहर स्थित चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर और जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में स्थापित विद्युत उपकरणों, वायरिंग, कंट्रोल पैनल, अर्थिंग व्यवस्था तथा सुरक्षा मानकों का बारीकी से परीक्षण किया गया। टीम ने कई बिंदुओं पर आवश्यक सुधार की जरूरत बताते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द कमियां दूर करने के निर्देश दिए। विद्युत सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान यह देखा गया कि अस्पतालों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित

और मानकों के अनुरूप रहे, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। टीम ने विशेष रूप से बिजली के पैनल, केबलिंग, अर्थिंग और सुरक्षा उपकरणों की स्थिति



का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से विद्युत प्रणाली का परीक्षण कराने और आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित करने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए कि जहां भी तकनीकी

कमियां हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाए। साथ ही विद्युत सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विद्युत सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थानों में विद्युत सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। समय-समय पर ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे और निर्धारित मानकों का पालन न करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विद्युत सुरक्षा अधिकारी के साथ उपखंड अधिकारी तथा जूनियर इंजीनियर अमरदीप सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सम्पूर्ण समाधान दिवस: शिकायतों का गुणवत्तापरक, समयबद्ध निस्तारण करें अफसर: डीएम

कृष्ण कुमार शुक्ला लखीमपुर खीरी। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सोमवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉ. ख्याति गर्ग, सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने तहसील गोला गोकर्णनाथ में 'संपूर्ण समाधान दिवस' में आये हुए फरियादियों के समस्याओं की गम्भीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए



सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्रम और रोजगार कानून डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ जनसमस्याओं का निस्तारण करते हुए गरीब व पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल न्याय दिलाते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शासकीय योजनाओं से आच्छादित कर मा. मुख्यमंत्री के निर्देशों को अमलीजामा पहनाया जाय। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले

प्रत्येक पीड़ित की समस्या को गंभीरता से सुनकर समयबद्ध और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ता से स्वयं संवाद कर उनकी मनोदशा को समझते हुए सहायता प्रदान की जाए। डीएम ने कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में है, इसलिए सभी अधिकारी रुचि लेकर गुणवत्तायुक्त ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। भूमि संबंधी मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीमों मौके पर जाकर गुणवत्तापरक निस्तारण करें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल ८४ शिकायती प्रार्थना पत्र पंजीकृत किये, जिसमें

०७ शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व ४७, पुलिस ११, आपूर्ति ०७, विकास ०४, विद्युत ०३, बैंक ०२, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ०१ और अन्य की ०६ शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें पृष्ठांकित कर सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण हेतु उपलब्ध करा दिया गया। इस दौरान एसडीएम युगांतर त्रिपाठी, सीओ अरुण कुमार सिंह, महक शर्मा, पीडी डीआरडीए सतीश कुमार पाण्डेय, डीडीओ गजेन्द्र प्रताप सिंह, तहसीलदार भीमसेन सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

डीआरएम गौरव अग्रवाल ने लखीमपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, व्यापार मंडल ने रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर सौपा ७ सूत्रीय ज्ञापन

लखीमपुर खीरी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) गौरव अग्रवाल ने सोमवार को लखीमपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दोपहर करीब १२:३० बजे स्टेशन पहुंचकर उन्होंने यात्री सुविधाओं, साफ-सफाई, प्लेटफर्म एवं स्टेशन परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ छोटी-मोटी कमियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उन्हें शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में डीआरएम ने कहा कि स्टेशन की अधिकांश व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और मिली कमियों को जल्द ठीक कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी.) के पदाधिकारियों ने डीआरएम को ७ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर पीलीभीत-मैलानी-सीतापुर रेलखंड पर रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की। व्यापार मंडल ने कहा कि बड़ी रेल लाइन शुरू होने के वर्षों बाद भी इस रेलखंड पर एक्सप्रेस

ट्रेनों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में लखीमपुर से नई दिल्ली एक्सप्रेस



ट्रेन चलाने, मैलानी-कानपुर इंटरसिटी सेवा शुरू करने, गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस का विस्तार करने, हावड़ा-अमृतसर मार्ग की ट्रेन का संचालन कराने सहित सात प्रमुख मांगें शामिल हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि बेहतर रेल सेवाओं से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर रेलवे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

खेल संस्कृति से बनेगा स्वस्थ और नशामुक्त समाज, सीएम योगी बोले-खिलाड़ियों को मिल रही बेहतर सुविधाएं

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। उनका कहना है कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और नशामुक्त समाज के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी हैं। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शूक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में उन्होंने प्रदेश की खेल उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ६५वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की पुरुष टीम ने २० पदक जीतकर पहली बार चैंपियन बनने का इतिहास रचा है। इसके अलावा जापान में आयोजित पुरुष अंडर-१८ हॉकी एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में उत्तर प्रदेश के पांच खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका

रही। उन्होंने प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, पैरालंपिक हाई जंप खिलाड़ी प्रवीण कुमार, भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी, दृष्टिबाधित धाविका सिमरन शर्मा और शतरंज ग्रैंडमास्टर



वंतिका अग्रवाल जैसी प्रतिभाएं आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'चैंपियन एक दिन में नहीं बनते और खेल संस्कृति भी रातोंरात तैयार नहीं होती।' इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के कौशल विकास, आधुनिक प्रशिक्षण और विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं के विस्तार पर लगातार कार्य कर

रही है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में भी अवसर दिए जा रहे हैं। खेल अवसंरचना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय लगभग बनकर तैयार है, जबकि प्रदेश के सभी मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि खेल न केवल करियर के नए अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का सबसे प्रभावी माध्यम भी हैं। उन्होंने कहा कि खेल स्वास्थ्य, अनुशासन, समर्पण, सहयोग और सफलता का संगम हैं। उन्होंने 'खेलोगे तो खिलोगे' का संदेश दोहराते हुए कहा कि खेल को बच्चों और युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इससे न केवल उनका सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को भी नई मजबूती मिलेगी।

‘अल्फा’ ने पहले सप्ताहांत में ५७ करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की

मुम्बई। आलिया भट्ट और शरवरी अभिनीत फिल्म 'अल्फा' ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में दुनियाभर के सिनेमाघरों की टिकट खिड़की पर ५७.६० करोड़ रुपये की कमाई की। निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। शिव रवेल के

खुफिया एजेंटों की कहानी पर आधारित है, जिनके किरदार आलिया भट्ट और शरवरी ने निभाए हैं। फिल्म में ये दोनों एजेंट एक खतरनाक दुश्मन (बॉबी देओल का किरदार) का मुकाबला करने के लिए एक बड़े अभियान



निर्देशन में बनी और यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) द्वारा निर्मित "अल्फा", इस स्टूडियो की जासूसी कहानियों पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाएं महिला कलाकारों ने निभाई हैं। निर्माताओं ने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट साझा कर फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए। पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'अल्फा' के हमारे दर्शकों के लिए 'अल्फा-प्यार'। एक्शन, संगीत और रोमांच से भरपूर 'अल्फा' सिनेमाघरों में देखिए। अपने टिकट अभी बुक करें। यह फिल्म दो विशिष्ट

पर निकलती हैं। फिल्म में अनिल कपूर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, जबकि ऋतिक रोशन विशेष भूमिका में जासूस कबीर धारीवाल के अपने किरदार को दोहराते नजर आए हैं। "अल्फा" यशराज फिल्म्स की जासूसी कहानियों पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला की नवीनतम फिल्म है, जिसमें इससे पहले "एक था टाइगर", "टाइगर जिंदा है", "वॉर", "पठान", "टाइगर ३" और "वॉर २" जैसी फिल्में शामिल हैं। यह फिल्म शुक्रवार को देश भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई।

इब्राहिम अली खान के साथ ‘दिलेर’ से डेब्यू की चर्चा तेज

लखनऊ। दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीलीला के ब लीवुड डेब्यू को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। पहले उनके कार्तिक आर्यन के साथ हिंदी फिल्मों में पदार्पण करने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार वह इब्राहिम अली खान के साथ फिल्म 'दिलेर' से ब लीवुड में कदम रख सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्तिक आर्यन और निर्देशक अनुराग बसु की प्रस्तावित रोमांटिक फिल्म फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसके बाद श्रीलीला के ब लीवुड डेब्यू की योजना में बदलाव होने की चर्चा है। अब कहा जा रहा है कि वह निर्देशक कुनाल देशमुख के निर्देशन में बन रही फिल्म 'दिलेर' के जरिए हिंदी सिनेमा में अपनी नई शुरुआत कर सकती हैं। फिल्म 'दिलेर' का निर्माण मैड क फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है। हालांकि,

महिला की हत्या के आरोप में पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज

अखिलेश दुबे
लखनऊ। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और बेटे की चाह में एक विवाहिता की कथित हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के भाई नागेंद्र सिंह की



तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थना पत्र के अनुसार, अनौरा अमौसी निवासी रेशम यादव का विवाह वर्ष २०१६ में हंसखेड़ा निवासी राजवीर यादव से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति राजवीर यादव, ससुर दिनेश यादव, सास सांवरे सूरी और बड़ी ननद शालिनी यादव कम दहेज लाने और बेटा न होने को लेकर रेशम को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। रेशम की तीन बेटियां हैं, जिसके कारण ससुराल पक्ष उसे और अधिक प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि २८ जून २०२६ की सुबह सभी आरोपियों ने एक राय होकर रेशम की पिटाई की और उसके गले में रस्सी कसकर उसे मारने का प्रयास किया। गंभीर हालत में

उसे लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान १ जुलाई को उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई का आरोप है कि अस्पताल में रेशम ने होश में आने पर अपने पति, सास, ससुर और ननद पर हत्या के प्रयास और मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में पारा पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतका की तीनों नाबालिग बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी कार्रवाई की मांग की गई है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

संजय बाजपेई

सीतापुर

मो.9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

सुरेश नारायण मिश्र

क्षेत्रीय सम्पादक

सौरभ कुमार, बिहार

मो.09386075289

मो० अरशद

ब्यूरो चीफ

मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा साईं आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन

भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar @yahoo.in

adbhut_samachar @rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक